भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †4028

उत्तर देने की तारीख- 19/12/2024

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

†4028. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास तेलंगाना के चेवेल्ला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय की वर्तमान जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए एक नया एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कार्यान्वयन की समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ईएमआरएस स्थापित करने के स्थान और व्यवहार्यता को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड क्या हैं; और

(घ) चेवेल्ला क्षेत्र में एसटी समुदाय की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ): भारत सरकार ने तेलंगाना सहित अनुसूचित जनजाति समुदायों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

(i). जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। नई योजना के तहत, 440 ईएमआरएस अनुमोदित किए गए हैं, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस होगा। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के तहत 2018 से पहले स्वीकृत किए गए 288 ईएमआरएस स्कूलों के साथ, तेलंगाना सहित 728 ईएमआरएस अनुमोदित किए गए हैं। स्वीकृत ब्लॉकों में, राज्य सरकार को भार मुक्त उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक है। आज तक 715 स्कूल स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 476 ईएमआरएस कार्यरत हैं, जिनसे 1,33,929 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। तेलंगाना राज्य में 23 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं और वे सभी क्रियाशील हैं।

इसके आगे चेवेल्ला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तेलंगाना में दो जिले शामिल हैं: विकाराबाद और रंगा रेड्डी। हालांकि, इन दोनों जिलों में से कोई भी ब्लॉक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्थापित करने के लिए दोहरे मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

(ii). धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा: 22,823 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय के साथ एक योजना 2 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई थी। डीएजेजीयूए में शिक्षा क्षेत्र सहित सामाजिक बुनियादी ढांचे में गंभीर अंतरों को भरने (संतृप्ति) की परिकल्पना है। इस योजना के तहत, 1000 छात्रावासों के निर्माण का प्रावधान किया गया है, जिससे शिक्षा तक पहुँच में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, डीएजेजीयूए के तहत जनजातीय बच्चों के लिए राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे आश्रम विद्यालयों और छात्रावासों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन का प्रावधान है।
(iii). जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के बीच बुनियादी और उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए तेलंगाना सहित पूरे देश में निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं क्रियान्वित (लागू) कर रहा है: -

क) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X के लिए):
ख) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर के लिए):

ग) अजजा छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (जिसे पहले शीर्ष श्रेणी छात्रवृत्ति योजना के रूप में जाना जाता था): प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून आदि जैसे पेशेवर क्षेत्रों में 265 शीर्ष श्रेणी के सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

घ) अजजा छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना: भारत में एम.फिल या पीएचडी करने के लिए मेधावी अजजा छात्रों को छात्रवृत्ति।

ङ) अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति: विदेश में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी अनुसूचित जनजाति (अजजा) छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।
मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं ओपन एंडेड हैं और 2.5 लाख तक की आय वाले प्रत्येक अजजा छात्र इन योजनाओं का लाभ उठा सकता है।

(iv). समग्र शिक्षा के तहत, स्कूल शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा 2,94,283 रुपये (2021-2026) के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ स्कूली शिक्षा के लिए एक व्यापक कार्यक्रम, कार्यान्वित किया जाता है। यह योजना स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को पाटने पर विशेष जोर देती है। इस योजना के अंतर्गत पीएम जनमन के तहत पीवीटीजी बच्चों सहित दुर्गम क्षेत्रों के लिए छात्रावास स्थापित करने का प्रावधान है। तेलंगाना के लिए पीएम जनमन के तहत 8 छात्रावास और डीएजेजीयूए के तहत 4 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जो चेवेल्ला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले लोगों सहित तेलंगाना के जनजातीय बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाएंगे।

*****